



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2000/वैशाख 18, 1922

No. 53]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2000/VAISAKHA 18, 1922

यूनियन बैंक आफ इंडिया

प्रस्तावित विनियमों का प्रारूप

मुंबई, 28 अप्रैल, 2000

यूनियन बैंक आफ इंडिया सामान्य विनियम, 1998

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के उपरांत तथा भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

अध्याय I

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (i) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सामान्य विनियम, 1998 कहा जाएगा.
- (ii) ये विनियम सरकारी गजट में इन्हें प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे.

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (ए) "अधिनियम" का तात्पर्य बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 के 5) से है.

- (बी) "बैंक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है.
- (सी) "बोर्ड" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित निदेशक बोर्ड से है.
- (डी) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है.
- (ई) "समिति" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली समिति से है.
- (एफ) "कार्यपालक निदेशक" से तात्पर्य प्रबंध निदेशक से भिन्न पूर्णकालिक निदेशक से है.
- (जी) "महाप्रबंधक" से तात्पर्य बैंक के महाप्रबंधक से है.
- (एच) "प्रबंध समिति" से तात्पर्य योजना के खण्ड 13 के अधीन गठित समिति से है.
- (आई) "प्रबंध निदेशक" से तात्पर्य बैंक के प्रबंध निदेशक से है.
- (जे) "रजिस्टर" से तात्पर्य बैंक की एक या उससे अधिक पुस्तकों में रखे गये शेयर धारक के रजिस्टर से है तथा इसमें अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 जी) के अधीन कम्प्यूटर फ्लॉपी या डिस्कटैप में रखे गये शेयरधारक के रजिस्टर शामिल है.
- (के) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य बैंक द्वारा निम्न कार्यों हेतु नियुक्त व्यक्ति से है:
- i) निर्गम से संबंधित निदेशकों से आवेदन एकत्रित करना.
 - ii) नियेशकों से प्राप्त आवेदनों एवं धनराशि या प्रतिभूतियों के विक्रेताओं को दी गयी धनराशि का समुचित रिकार्ड रखना.
 - iii) निम्नलिखित कार्यों में बैंक की मदद करना:
 - ए) शेयर बाजार के परामर्श से प्रतिभूतियों के आवंटन का आधार निर्धारित करना.
 - बी) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करना.
 - सी) निर्गम के संबंध में आवंटन पत्र, धन वापसी आदेश या प्रमाणपत्र या अन्य संबंधित प्रपत्रों की प्रोसेसिंग एवं प्रेषण कार्य करना.
 - iv) बैंक द्वारा समय-समय सौंपे गये अन्य कार्य:
- (एल) "योजना" से तात्पर्य राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध प्रायधान) योजना 1970 से है.
- (एम) "शेयर" से तात्पर्य बैंक की शेयर पूंजी में शेयर से है.
- (एन) शेयर अंतरण एजेंट में शामिल है—
- (i) कोई भी व्यक्ति, जो बैंक की ओर से बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के धारकों का रिकार्ड का रखरखाव करता है तथा इसकी प्रतिभूतियों के अन्तरण तथा प्रतिदान से संबंधित सभी मामलों में व्यवहार करता है.
 - (ii) बैंक का कोई विभाग या संविभाग (किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला) जो उप-खण्ड (i) में संदर्भित गतिविधियों संबंधी कार्य करता है.
- (ओ) अध्याय III में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है परंतु डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में परिभाषित किया गया है, का तात्पर्य उक्त अधिनियम में उल्लेख के अनुसार ही माना जाएगा.
- (पी) प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियां जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम या योजना में परिभाषित किया गया है, का तात्पर्य क्रमशः यही होगा जैसा अधिनियम या योजना में उल्लेख किया गया है.

अध्याय II

शेयर एंव शेयर रजिस्टर

3. शेयरों की प्रकृति

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर चल संपत्ति होंगे और अन्य हस्तांतरण इन विनियमों में दिये गये तरीके से हो सकेगा.

4. शेयर पूंजी के प्रकार

- (I) अधिमानी शेयर पूंजी का तात्पर्य यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी का वह हिस्सा है जो निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी करता हो:
- (ए) लाभांश के संबंध में, इन्हें नियत राशि या नियत दर पर परिकल्पित राशि प्राप्त करने का अधिमानी अधिकार हो जो आयकर से मुक्त अथवा आयकर के अधीन हो सकता है.
- (बी) पूंजी के संबंध में, समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान के मामले में, चुकता की गयी या चुकता की गयी मानी गयी पूंजी के पुनर्भुगतान का अधिमानी अधिकार हो, भले ही निम्नलिखित दोनों राशियों के भुगतान का अधिमानी अधिकार हो अथवा नहीं.
- ए. परिसमापन या पूंजी के भुगतान की तिथि तक खण्ड (ए) में निर्दिष्ट राशि से संबंधित किसी धन के अदत्त रहने पर,
- बी. केन्द्र सरकार की पूर्ण सहमति से बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी नियत प्रीमियम या किसी नियत दर पर प्रीमियम,
- (II) "सांख्यिक शेयर पूंजी" से तात्पर्य उस पूंजी से है जो अधिमानी शेयर पूंजी नहीं है.
- (III) "अधिमान प्राप्त शेयर" और "सांख्यिक शेयर" शब्दों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा.

5. रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने वाले ब्यौरे

- (I) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (एफ) के अनुसार एक शेयर रजिस्टर रखा जाएगा, उसका रखरखाव किया जाएगा और अद्यतन रखा जाएगा.
- (II) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2(एफ) में निर्दिष्ट ब्यौरों के अलावा ऐसे अन्य ब्यौरे 'जिन्हें बोर्ड निर्दिष्ट करें', रजिस्टर में प्रविष्ट किये जायेंगे.
- (III) किसी शेयर के संयुक्त धारक होने की दशा में उप विनियम (I) की अपेक्षानुसार उनके नाम और अन्य ब्यौरे से संयुक्त धारकों के प्रथम नाम के साथ समूहित किये जायेंगे.
- (IV) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (डी) के परंतुक के अधीन भारत के बाहर का निवासी कोई शेयर धारक बैंक को भारत में स्थित पता दे सकता है तथा उस पते को रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा और अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्य से उसे पंजीकृत पता माना जाएगा.
- (V) बैंक द्वारा ट्रस्ट से संबंधित अन्तर्निहित या प्रलक्षित कोई भी नोटिस न तो प्राप्त की जाएगी और न ही रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी.

6. शेर और रजिस्ट्रों पर नियंत्रण

अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधान तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अधीन रजिस्टर युनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यालय में रखा जाएगा और यही उसका रखरखाव किया जाएगा तथा बोर्ड के नियंत्रण में रहेगा तथा किसी व्यक्ति के शेरधारक के रूप में पंजीकृत होने की पात्रता के बारे में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा.

7. ऐसे पत्रकार, जिन्हें शेरधारक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा

- (I) इन विनियमों द्वारा किये गये अन्यथा प्रावधानों का छोड़कर, वे व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम नहीं है, शेर धारक के रूप में पंजीकृत किये जाने के पात्र नहीं होंगे तथा इस संबंध में बोर्ड का निर्णय निर्णायक व अंतिम होगा.
- (II) फर्मों के मामले में, शेर अलग-अलग भागीदारों के नाम से पंजीकृत किये जा सकेंगे तथा कोई भी फर्म शेर धारक के रूप में पंजीकृत किये जाने की पात्र नहीं है.

8. कम्प्यूटर प्रणाली में शेर रजिस्टर का रखरखाव करना

- (I) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (एफ) व विनियम 5 में उल्लिखित शेर रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने वाले विवरण का रखरखाव अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (जी) के अंतर्गत डिस्कट, फ्लॉपी, कार्टिज के द्वारा मैग्नेटिक /ऑप्टिकल/मैग्नेटो-ऑप्टिकल मीडिया के रूप में (जिसे इसके बाद मीडिया कहा जाएगा) कम्प्यूटर में केन्द्रीय कार्यालय में किया जाएगा तथा इसका बैकअप उस स्थान पर रहेगा जिसका निश्चय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इसके निमित्त पदनामित अधिकारी, जो महाप्रबंधक से नीचे संयर्ग का नहीं होगा, (इसे बाद में पदनामित अधिकारी कहा जाएगा) करेंगे.
- (II) डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 की धारा 11 सह पठित अधिनियम की धारा 3 (जी) के अंतर्गत शेर रजिस्टर में दर्ज किये जाने वाले विवरण का रखरखाव उनमें विहित प्रारूप और तरीके से किया जाएगा.

9. कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा के उपाय

- (I) विनियम 8(I) के अनुसार आंकडा संग्रहीत करने के लिए बनायी गयी कम्प्यूटर प्रणाली में पहुँच, निर्गम के रजिस्ट्रार और शेर अंतरण एजेंट सहित ऐसे व्यक्तियों तक प्रतिबंधित होगी जिन्हें इसके लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाये और इसका पासवर्ड, यदि कोई हो, और इलेक्ट्रॉनिक, सुरक्षा, नियंत्रण पद्धति को इन व्यक्तियों की अभिरक्षा में गोपनीय रखा जाएगा.
- (II) प्राधिकृत व्यक्तियों की पहुँच का रिकार्ड कम्प्यूटर प्रणाली की लॉग में रखा जाएगा तथा इस लॉग को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा इसके लिए पदनामित अधिकारी/व्यक्ति के पास सुरक्षित रखा जाएगा.
- (III) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये अंतराल पर शेर होल्डर रजिस्टर में किये गये परिवर्तनों को समाहित करते हुए हटाये जा सकने वाले मीडिया पर बैकअप की प्रतिलिपि तैयार की जायेगी. इसकी कम से कम एक प्रति उस स्थल से अलग अन्य स्थल पर रखी जायेगी जहाँ प्रोसेसिंग की जा रही हो. ये प्रतियाँ अग्निरोधी, तापनियंत्रित, तथा तालाबंद परिवेश में रखी जायेगी. दोनों ही स्थलों पर बैकअप तक पहुँच, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित होगी. प्राधिकृत व्यक्ति उस स्थान पर रखे मेन्सअल रजिस्टर में प्रवेश (पहुँच) का रि 1st रखेंगे

- (IV) प्राधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह बैंक-अप की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग कर बैंक अप पर लिये गये आंकड़ों का मिलान कम्प्यूटर प्रणाली के आंकड़ों से करे. इस परिचालन के परिणाम एतदर्थ रखे गये रजिस्टर में रिकार्ड किये जायें.
- (V) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस के लिए सक्षम है कि वे तकनीक के उन्नयन और/या स्थिति की अनिवार्यताओं को देखते हुए कम्प्यूटर प्रणाली में सुरक्षा के उपायों के बारे में विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अनुदेशों, शर्तों में वृद्धि कर दे या संशोधित कर दे.

10. संयुक्त शेयरधारियों के अधिकारों का प्रयोग

किसी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में होने पर, शेयर के अंतरण के अलावा, वोट देने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस की तामील किये जाने तथा यूनियन बैंक से संबंधित किसी अन्य और सभी मामलों में रजिस्टर में प्रथम नामवाला व्यक्ति उसका एकमात्र धारक माना जायेगा.

11. रजिस्टर का निरीक्षण

- (i) विनियम 12 के तहत बंद रहने की अवधि के सिवाय, यह रजिस्टर किसी भी शेयर धारक द्वारा निशुल्क निरीक्षण के लिए, इसके रखरखाव किये जाने के स्थान पर बोर्ड द्वारा लगाई गई पाबंदियों के अधीन कारोबार समय में लेकिन प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 2 घंटे की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा.
- (ii) कोई भी शेयर धारक रजिस्टर या कम्प्यूटर प्रिंट की किसी प्रविष्टि का सार निशुल्क ले सकता है या उसे रजिस्टर के कम्प्यूटर प्रिंट या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि की आवश्यकता होने पर प्रतिलिपि किये जाने वाले प्रति 100 शब्द या उसके किसी हिस्से के लिए रु.5/- प्रति की दर से पूर्व भुगतान करने पर प्रतिलिपि प्रदान की जायेगी.
- (iii) उप विनियम (ii) में किसी भी बात के होते हुए भी सरकार के किसी भी विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि करने का या रजिस्टर या उसके किसी भी हिस्से की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार होगा.

12. रजिस्टर का बंद रहना

बैंक, भारत में प्रचलित कम से कम 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये कम से कम 7 दिन का नोटिस देकर शेयरधारकों के रजिस्टर को प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर 45 दिनों से अनधिक अवधि तथा एक अवसर पर 30 दिनों से अनधिक अवधि के लिए आवश्यकतानुसार बंद रख सकता है.

13. शेयर प्रमाण पत्र

- (i) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में होगा जिसमें शेयर प्रमाणपत्र संख्या, अलग-अलग संख्या, शेयरों की संख्या जिसके लिए जारी किया जा रहा है, तथा उस शेयरधारक का नाम जिसे यह जारी किया जा रहा है अंकित होगा.
- (ii) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर बोर्ड के संकल्प के अनुसार में 'कॉमन सील' अंकित होगी तथा उस पर 2 निदेशकों और बोर्ड द्वारा इस उद्देश के लिए नियुक्त अन्य

निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्रैफ़ या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अंकित किये गये हो सकते हैं।

- (iii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्रैफ़ या किसी अन्य तरीके से अंकित किया गया हस्ताक्षर उसना ही मान्य होगा जितना हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने उचित हस्तालेख में किया गया हस्ताक्षर वैध होगा।
- (iv) कोई भी शेयर प्रमाणपत्र तब तक मान्य नहीं होगा जब तक उस पर इस प्रकार का हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाणपत्र मान्य एवं बाध्यकारी होगा भले ही उसके जारी होने से पूर्व उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का बैंक की ओर से उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार ही समाप्त हो जाए।
- (v) यदि इस प्रकार तैयार किए गए शेयर प्रमाणपत्र पर उपखण्ड (ii) में उल्लेख के अनुरूप ऐसे अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है, जो शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के समय जीवित नहीं है, तो बैंक उसके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली प्रणाली से उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर निरस्त कर सकती है तथा उसके ऊपर किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकती है। इस प्रकार जारी किया गया प्रमाणपत्र मान्य होगा।

14. शेयर प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना

- (i) बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शेयरधारक को शेयर जारी करते समय उसके नाम से एक समय पर पंजीकृत प्रत्येक 100 शेयरों या उसके गुणजों में जारी शेयरों के लिए एक शेयर प्रमाणपत्र जारी करें तथा उससे अधिक शेयरों की संख्या, परंतु जो सी से कम है, के लिए एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र जारी करे।
- (ii) यदि पंजीकृत किये जाने वाले शेयरों की संख्या एक सौ से कम है तो सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा,
- (iii) कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से कोई शेयर या शेयरों के रखे जाने के संबंध में, बैंक एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए, बाध्य न होगा और संयुक्त धारकों में से किसी एक को शेयर के प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी, ऐसे सभी धारकों के लिए पर्याप्त सुपुर्दगी होगी।

15. शेयर प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण

- (i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र फट गया या विकृत हो गया है तो बोर्ड या इसके लिए नामित समिति, ऐसे प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर उसे रख करने तथा उसके स्थान पर एक नया प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दे सकती है।
- (ii) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र खोया या नष्ट हुआ सूचित किया जाता है तो बोर्ड या उसके द्वारा नामित समिति प्रतिभू के साथ या उसके बिना जैसा भी बोर्ड या समिति उचित समझे, क्षतिपूर्ति बांड लेकर दो समाचार पत्रों में इसकी सूचना प्रकाशित कर और यूनिवर्स बैंक ऑफ इंडिया को इसकी लागत, प्रभारों और व्ययों के भुगतान पर, ऐसे खोये या नष्ट हुए प्रमाणपत्र के हकदार व्यक्ति को उसके स्थान पर एक डुप्लिकेट प्रमाणपत्र दे सकती है।

16. शेयरों का समेकन और उपविभाजन

शेयर धारक(कों) द्वारा लिखित आवेदन करने पर, बोर्ड या उसके द्वारा नामित समिति समेकन/उपविभाजन, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रस्तुत शेयरों को समेकित/उपविभाजित कर सकती है और बैंक को उनके स्थान पर इसकी लागत, प्रभारों और इससे संबंधित प्रासंगिक प्रभारों का भुगतान कर नये प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।

17. शेयरों का अंतरण

- (i) बैंक के शेयरों का प्रत्येक अंतरण, इसके साथ फ़ॉर्म 'ए' के रूप में संलग्न अंतरण लिखत द्वारा या बैंक प्रायः समय-समय पर

अनुमोदित ऐसे ही अन्य रूप से शेयर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करने पर होगा और जिस पर विधिवत् टिकट लगाई गई हो, तारीख अंकित हो और अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा या उनकी ओर से विधिवत् निष्पादित हो।

- (ii) शेयर प्रमाणपत्र के साथ, अंतरण लिखत बैंक को इसके प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अंतरणकर्ता, तब तक ऐसे शेयर का धारक माना जाएगा जब तक कि इसके संबंध में अंतरिती का नाम शेयर, रजिस्टर में दर्ज नहीं कर लिया जाता है।
- (iii) बैंक द्वारा शेयर प्रमाणपत्र के साथ किसी अंतरण लिखत द्वारा अंतरण को पंजीकृत करने के अनुरोध की प्राप्ति पर, बोर्ड या बोर्ड द्वारा नामित समिति, शेयर प्रमाणपत्र के साथ उक्त लिखत को रजिस्ट्रार और/या शेयर अंतरण एजेंट को यह सत्यापन करने के उद्देश्य से अग्रसारित करेगा कि सभी तकनीकी अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन किया गया है, रजिस्ट्रार और/या शेयर अंतरण एजेंट, शेयर प्रमाणपत्र, यदि कोई है, के साथ अंतरण लिखत अंतरिती को पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए वापस करेगा यदि :
- (ए) अंतरण लिखत पर विधिवत् टिकट बगैर व समुचित रूप से उसे निष्पादित किये बगैर पंजीकरण हेतु बैंक को प्रस्तुत किया गया है तथा इसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र व अन्य ऐसे सभी साक्ष्य नहीं लगाए गए हैं, जिनकी अंतरणकर्ता के हक को दर्शाने के लिए बोर्ड अपेक्षा करे।
- (बी) पंजीकृत इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अंतरण लिखत द्वारा 'कवर' किये गए शेयरों के संबंध में अंतरिती, बैंक का शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।
- (iv) बोर्ड या बोर्ड द्वारा नामित समिति जब तक विनियम 19 के अधीन अंतरण के पंजीकरण को अस्वीकार नहीं करती है, तब तक अंतरण का पंजीकरण किये जाने योग्य है।

18. अंतरण को निलंबित करने का अधिकार : बोर्ड या बोर्ड द्वारा नामित समिति रजिस्टर के बंद होने की अवधि के दौरान कोई अंतरण पंजीकृत नहीं करेगी।

19. शेयरों के अंतरण के पंजीकरण को अस्वीकार करने का बोर्ड का अधिकार

(i) बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों को छोड़कर अन्य किसी आधार पर अंतरिती के नाम शेयरों के अंतरण को मना नहीं कर सकता है :

- (ए) यदि शेयरों का अंतरण अधिनियम या उसके तहत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया है या अन्य किसी कानून या किसी ऐसे अंतरण के पंजीकरण से संबंधित कानून में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।
- (बी) बोर्ड के मत में शेयरों का अंतरण, बैंक और जनहित के विरुद्ध है।
- (सी) शेयरों का अंतरण न्यायालय के आदेश, ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) या तत्समय प्रवृत्त कानून के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
- (डी) भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति या कंपनी अथवा भारत में लागू नहीं होने वाली किसी अधिनियम के तहत निगमित कोई कंपनी या उसकी कोई शाखा चाहे भारत से बाहर निवासी हो या न हो, अंतरण अनुमत होने के परिणामस्वरूप बैंक के शेयर धारित या प्राप्त करने पर उनका सकल निवेश, बैंक की चुकता पूंजी के 20% से अधिक या सरकारी गजट में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।

तथापि उप विनियम (1)(सी) में उल्लिखित मना करने की शक्ति का उपयोग बोर्ड द्वारा नामित समिति द्वारा किया जा सकता है।

(ii) बैंक के शेयरों के अंतरण का लिखत इसके पंजीकरण हेतु प्राप्त करने के बाद बोर्ड यह तय करेगा कि उप विनियम (1) में उल्लिखित किसी आधार पर उक्त पंजीकरण को अस्वीकृत किया जाए या नहीं :

- (ए) यदि इसने तय किया है कि ऐसा पंजीकरण अस्वीकृत नहीं किया जाना है तो ऐसा पंजीकरण प्रभावी माना जाए; और
- (बी) यदि इसने तय किया है कि ऐसा पंजीकरण उप विनियम (1) में उल्लिखित किसी आधार पर अस्वीकृत किया जाना है तो अंतरण फार्म की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर अंतरणकर्ता और अंतरिती को लिखत नोटिस देगा।

20. मृत्यु, दिवालियेपन इत्यादि घटना पर शेयरों का प्रेषण

- (i) कियी शेयर के मामले में, मृत शेयर धारक के निष्पादन या प्रशासक अथवा प्रोबेट पत्र के धारक या वसीयत के साथ या उसके बिना प्रशासन के पत्रों या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग 10 के अधीन जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या किसी विधिक अभ्यावेदन के धारक को या मृतक द्वारा अपने जीवनकाल में जिस व्यक्ति के पक्ष में विधिमान्य अंतरण लिखित निष्पादित किया गया था, उसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऐसे शेयर रखने का हकदार माना जाएगा।
- (ii) दो या अधिक शेयर धारकों के नाम से पंजीकृत शेयरों के मामले में उत्तरजीवी तथा उत्तरजीवियों और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर, उसके निष्पादकों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र वसीयत के साथ या उसके बिना शेयर के संबंध में उत्तरजीवी के हितों को दर्शाता या प्रशासकों अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति जो प्रोबेट पत्रों या प्रशासन पत्रों का धारक या अन्य कोई विधिक प्रतिनिधि या व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसे व्यक्ति द्वारा शेयर अंतरण का वैध लिखित निष्पादित किया गया और अंतिम उत्तरजीवी के जीवनकाल के दौरान ऐसा अंतिम उत्तरजीवी एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऐसे शेयर पर हक की मान्यता देगा।
- (iii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को तब तक मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि उन्हें यथास्थिति प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय से प्राप्त नहीं हो गया हो, तथापि बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने पर, क्षतिपूर्ति या अन्य किसी शर्तों पर प्रोबेट पत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या किसी अन्य प्रकार के विधिक प्रतिनिधित्व के प्रस्तुतीकरण से छूट प्रदान करना न्यायोचित होगा।
- (iv) किसी शेयर धारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप उसके शेयर के लिये किसी ऐसे व्यक्ति के हकदार होने पर और किसी शेयर धारक के दिवालियेपन, शोधन अक्षमता (दिवाला) या परिसमापन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के शेयर के हकदार होने पर वह ऐसे साक्ष्य, जैसा कि बोर्ड अपेक्षा करे, के प्रस्तुत करने पर उसे अधिकार है :
- (ए) ऐसे शेयर के संबंध में एक शेयर धारक के रूप में पंजीकृत होना।
- (बी) उक्त शेयर के अंतरण को ऐसा मानना कि अंतरणकर्ता उक्त शेयर का हकदार है।

21. पंजीकरण के लिए योग्य शेयरधारक की योग्यता समाप्त हो जाना : शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किसी व्यक्ति का चाहे एकल या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत हो, का यह कर्तव्य होगा कि उक्त पंजीयन की योग्यता समाप्त होने पर तुरंत, निदेशक बोर्ड को इसकी सूचना दे।
22. शेयरों पर मांग (कॉल) : बोर्ड, शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों पर शेष सारी अदत्त रकम के संबंध में जैसा वह उचित समझता है, समय-समय पर ऐसी मांग कर सकता है जो आबंटन की शर्तों के अनुसार निश्चित समय पर देय नहीं है और प्रत्येक शेयर धारक, इस प्रकार की गई प्रत्येक मांग के लिए बोर्ड द्वारा नियत व्यक्ति, समय और स्थान पर भुगतान करेगा, मांग का भुगतान किशतों में हो सकता है।
23. संकल्प की तिथि से मांग : किसी मांग का समय वह समय माना जाएगा जब ऐसी मांग करते हुए बोर्ड ने संकल्प पारित किया हो और उस तिथि को या बोर्ड द्वारा उसके विवेकाधिकार के अंतर्गत निश्चित ऐसी बाद की तिथि, पंजीकृत शेयर धारक द्वारा देय तिथि मानी जाएगी।
24. मांग की सूचना : प्रत्येक मांग पर भुगतान के समय को निर्दिष्ट करते हुए कम से कम 30 दिन की सूचना दी जाएगी, लेकिन ऐसी मांग के भुगतान के समय से पूर्व लिखित रूप में इसकी सूचना देकर बोर्ड इसे रद्द भी कर सकता है।
25. मांग के भुगतान के लिए समय का विस्तार : बोर्ड समय-समय पर और अपने विवेकानुसार किसी मांग के भुगतान के लिए निश्चित समय सभी के लिए या किसी एक शेयर धारक के लिए उसके आवास की दूरी के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से बढ़ा सकता है, किंतु कोई शेयर धारक उक्त अधिकार के रूप में समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं कर सकता है।
26. संयुक्त धारकों की देयताएं : किसी शेयर के संयुक्त धारक, उसकी सभी मांगों के भुगतान के संबंध में संयुक्त रूप से और पृथकतः उत्तरदायी होंगे।
27. मांग के रूप में निश्चित समय पर या किशतों में भुगतान योग्य राशि : यदि किसी शेयर की निर्गम की शर्त के अनुसार या अन्यथा किसी निश्चित समय पर या किशतों में निश्चित समय पर कोई राशि देय है तो प्रत्येक ऐसी राशि या किशत देय होगी मानो वह बोर्ड द्वारा विधिवत की गई मांग है और जिसकी उचित सूचना दी गई थी और तदनुसार ऐसी राशि या किशत के संबंध में मांगों के लिए यहां बनाये गए सभी प्रावधान लागू होंगे।

28. **मांग या किश्त पर ब्याज कब देय है :** यदि किसी मांग या किश्त के संबंध में देय राशि उसके भुगतान के लिए नियत दिन पर या उसके पूर्व भुगतान नहीं की जाती है तो उसके लिए उस शेयर का मौजूदा धारक या आबंटिती, उसके भुगतान के लिए नियत दिन से वास्तविक भुगतान के समय तक की अवधि के लिए उक्त राशि पर ऐसे ब्याज का भुगतान करेगा जो बोर्ड समय-समय पर निश्चित करे, लेकिन बोर्ड अपने विवेकानुसार ऐसे ब्याज के भुगतान को पूर्णतः या अंशतः माफ कर सकता है।
29. **शेयरधारकों द्वारा मांगों का भुगतान न करना :** जब तक कोई शेयरधारक उसके द्वारा एकल रूप से या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से धारित प्रत्येक शेयर के संबंध में लगाई गई और देय ब्याज व खर्च सहित बकाया व देय मांग का भुगतान नहीं कर देता है तब तक वह किसी भी लाभांश प्राप्त करने या शेयरधारक के किसी अधिकार के प्रयोग का अधिकारी नहीं होगा।
30. **मांग या किश्त का भुगतान न किये जाने की सूचना :** किसी शेयरधारक के भुगतान के लिए नियत तिथि को या उसके पहले, मांग या किश्त की पूर्ण राशि या उसके किसी अंश या किसी शेयर के संबंध में मूल या ब्याज का भुगतान करने में विफल रहने पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके उपरोक्त मांग या किश्त या उसके किसी अंश या किसी अन्य राशि के अदत्त रहने की अवधि या किसी न्यायिक निर्णय या डिक्री के पूर्णतः या उसके किसी अंश के भुगतान न होने की अवधि के दौरान, शेयरधारक या संचरण के दौरान शेयर के हकदार व्यक्ति को अदत्त रही ऐसी मांग या किश्त या उसके अंश या किसी अन्य धन और उस पर प्रोद्भूत हुई ब्याज तथा इस भुगतान न करने के कारण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भुगतान किये या व्यय किये सभी व्ययों (विधिक और अन्य) के भुगतान के लिए नोटिस दे सकता है।
31. **जब्ती की सूचना :** जब्ती की सूचना में एक नियत दिन का उल्लेख होगा जो सूचना की तिथि से 14 दिनों से कम नहीं होगा। उक्त सूचना में उन स्थान या स्थानों का भी नाम होगा जहाँ उक्त ऐसी मांग या किश्त अथवा उसके भाग या अन्य राशियों और ऐसे ब्याज और व्ययों का भुगतान किया जाना है। सूचना में इस बात का भी उल्लेख होगा कि नियत तिथि को या उसके पूर्व तथा नियत स्थान पर भुगतान न किये जाने पर जिस शेयर के लिए मांग की गई है या जिसकी किश्त देय है उसे जब्त किया जा सकेगा।
32. **भुगतान में चूक होने पर शेयर जब्त होना :** पूर्व कथित ऐसे किसी नोटिस की अपेक्षाओं का यदि अनुपालन नहीं होता है, तो ऐसे नोटिस देने के बाद कोई भी शेयर कभी भी संपूर्ण मांग या किश्तों, ब्याज और खर्चों या उससे संबंधित बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर तत्संबंधी बोर्ड संकल्प से जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी जब्ती में वे सभी लाभांश भी शामिल होंगे जो जब्त शेयरों के संबंध में घोषित तो हो चुके हैं किंतु जब्ती के पूर्व ठमका वास्तव में भुगतान नहीं हुआ है।
33. **रजिस्टर में जब्ती की प्रविष्टि :** विनियम 32 के तहत जब्त शेयर की प्रविष्टि जब्ती के दिनांक सहित रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
34. **जब्त शेयरों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति होना और इन्हें बेचा जा सकना :** ऐसे जब्त किये शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति माने जाएंगे और इन्हें बोर्ड द्वारा तय शर्तों और प्रक्रिया से बेचा, पुनः आबंटित या अन्य रूप में किसी व्यक्ति के पक्ष में निपटान किया जा सकता है।
35. **जब्ती रद्द करने का अधिकार :** बोर्ड, विनियम 32 के तहत जब्त शेयरों की जब्ती को, उनके विक्रय, पुनः आबंटित और/या निपटान किये जाने से पूर्व किसी भी समय, ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, रद्द कर सकता है।
36. **जब्ती के समय बकाया राशि एवं ब्याज देने हेतु शेयरधारी का उत्तरदायी होना :** कोई भी शेयरधारी जिसके शेयरों को जब्त कर लिया गया है, जब्ती के बावजूद, सभी मांगों, किश्तों, ब्याज, खर्चों या अन्य बकाया धनराशि या जब्ती के समय ऐसे शेयरों पर ब्याज सहित, जब्ती तिथि से उनके भुगतान तक, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दर पर भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को तत्काल भुगतान करेगा एवं बोर्ड उसे उसके पूर्णतः या आंशिक भुगतान के लिए विवश कर सकेगा।
37. **आंशिक भुगतान जब्ती को प्रतिबाधित नहीं करता :** किन्हीं शेयरों की बकाया मांग राशि और अन्य धन राशि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय या डिक्री हो जाना या उसके अंतर्गत कोई भुगतान या तुष्टि हो जाना या किन्हीं शेयरों के संबंध में भविष्य में समय-समय पर मूलधन और ब्याज के रूप में देय होने वाले धन के अंश को किसी शेयरधारी से प्राप्त करना या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसी धन राशि के संदर्भ में अदायगी के स्थगन की अनुमति देना इन विनियमों के तहत ऐसे शेयरों की जब्ती में बाधक नहीं होगा।
38. **शेयरों की जब्ती से बैंक के विरुद्ध सभी दावों का समाप्त होना :** शेयरों की जब्ती से, शेयर की जब्ती के समय से ही उन अधिकारों के अलावा जिन्हें इस विनियम के प्रावधान से स्पष्टतः अलग रखा गया हो, को छोड़ उन शेयरों में निहित सभी हित तथा बैंक के विरुद्ध मांग और दावे तथा शेयरों से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
39. **जब्ती के बाद विक्रय, पुनः जारी, पुनः आबंटन तथा निपटान पर मूल शेयरों का अकृत एवं शून्य होना :** पूर्ववर्ती विनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित शेयरों के संबंध में मूल रूप से जारी शेयर (यदि बैंक की मांग पर चूककर्ता ने इन्हें पहले ही सरंद्ध न किया हो) निरस्त होकर अकृत, शून्य और अप्रभावी होंगे। बोर्ड संबंधित शेयरों के बदले उसके पात्र व्यक्ति/यों को नये प्रमाणपत्र जारी करने को अधिकृत होगा।

40. जब्ती प्रावधानों का लागू होना : शेयर निर्गम की शर्तानुरूप नियम समय पर, अंकित या प्रीमियम के रूप में देय धनराशि, जैसे कि वह विधिवत् की गई मांग पर देय हुई हो, के भुगतान न करने के मामलों में इन विनियमों के जब्ती संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
41. शेयरों पर लियन :
- (I) निम्नलिखित स्थितियों में बैंक का प्रथम एवं सर्वोपरि लियन होगा :
- (ए) प्रत्येक शेयर पर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर न हो) उस शेयर के संबंध में सभी मांगी गई या निश्चित समय पर देय धनराशियों के लिए (भले ही वे देय वर्तमान हो या नहीं);
- (बी) एक व्यक्ति के नाम से पंजीकृत सभी शेयरों पर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर न हो) उसके द्वारा या उसकी संपदा पर बैंक को वर्तमान में देय सभी धनराशियों के लिए;
- (सी) बैंक के प्रति उसके ऋण, देयताओं और वचनबद्धताओं, भले ही उनके पूर्ण करने या उन्मोचित होने का वास्तव में समय हुआ हो या नहीं, हेतु प्रत्येक व्यक्ति के नाम से (अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से) पंजीकृत सभी शेयरों और उसके विक्रय आगमों पर तथा बैंक किसी भी शेयर पर अपने लियन के समकक्ष किसी अन्य हित को मान्यता नहीं देगा।
- (II) बैंक का लियन, यदि कोई है, तो वह उस शेयर पर देय सभी लाभांशों पर भी लागू होगा।
42. शेयरों की बिक्री द्वारा लियन लागू करना :
- (I) बोर्ड, ऐसी प्रक्रिया से, जिसे वह उचित समझे, कंपनी के लियन वाले किसी भी शेयर को बेच सकता है :
- (क) यदि वह राशि जिसके संदर्भ में लियन विद्यमान है, वर्तमान में देय है, और
- (ख) वर्तमान में देय उस धनराशि के संदर्भ में जिस पर कि लियन विद्यमान है, के बारे में शेयर के उस समय के पंजीकृत धारक को या उसको जो उसकी मृत्यु या दिवालिया होने पर उसका हकदार होता, लिखित में भुगतान की मांग का नोटिस देने के लिए 14 दिन की समाप्ति के बाद.
- (II) ऐसे किसी भी विक्रय को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड किसी अधिकारी को, बेचे गये शेयर इसके क्रेता को अंतरित करने के लिए अधिकृत कर सकता है.
43. शेयरों की बिक्री से प्राप्त आगमों का प्रयोग - विनियम 42 के तहत किसी शेयर के विक्रय से प्राप्त विरुद्ध आगम, ऐसे विक्रय की लागतों को कम करके उन ऋणों और देयताओं की तुष्टि हेतु प्रयुक्त किये जायेंगे जिनके लिए लियन विद्यमान हो और जो वर्तमान में देय है और शेष बची राशि, यदि कोई हो, तो शेयर धारकों अथवा किसी उस व्यक्ति को, भुगतान की जाएगी, जो ऐसे बेचे गये शेयर के संबंध में संघरण के दौरान अधिकारी है.
44. जब्ती का प्रमाणपत्र - इस हेतु विधिवत् प्राधिकृत किसी भी निदेशक या यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी यह लिखित प्रमाणपत्र कि शेयर के संबंध में मांग की गई और इस हेतु बोर्ड के संकल्प से शेयर जस्त किये गये, उन सभी के विरुद्ध, जो ऐसे शेयरों के हकदार हैं, निर्णायक साक्ष्य होगा.
45. जस्त शेयर के क्रेता और आवंटि का हक - यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया किसी शेयर के लिए दिए गये प्रतिफल को यदि कोई हो, उसके विक्रय, पुनः आवंटन तथा अन्य प्रकार से निपटान के समय प्राप्त कर सकेगा और उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा शेयर बेचा, पुनः आवंटित या जिसके पक्ष में निपटान किया गया है, उस शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा यह न तो प्रतिफल, यदि कोई हो, के उपयोग का ध्यान रखने के लिए बाध्य होगा और न ही जस्त

शेयर के विक्रय, पुनः आवंटन और शेयर के अन्य प्रकार से निपटान के संदर्भ में प्रक्रियागत अनियमितता अथवा अवैधता से शेयर पर उसका हक प्रभावित होगा, और इस विक्रय से व्यथित व्यक्ति के पास क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का ही एकमात्र उपचार होगा और वह भी केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विरुद्ध होगा.

46. शेयरधारकों को नोटिस अथवा प्रलेख भेजना -

(i) बैंक किसी भी शेयरधारी को उसके पंजीकृत पते पर अथवा यदि उसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है तो उस पते पर जो उसने भारत के अन्दर नोटिस भेजने के लिए बैंक को दे रखा है या तो व्यक्तिगत रूप से या साधारण डाक से नोटिस अथवा प्रलेख तामील कर सकता है.

(ii) दस्तावेज अथवा नोटिस को डाक से भेजे जाने पर, यदि उस पर उचित पता लिख दिया है, डाक शुल्क का भुगतान कर दिया है और पोस्ट कर दिया गया है, तो उसे भलीभाँति तामील हुआ माना जाएगा.

परंतु जहां शेयरधारी ने अग्रिम रूप से बैंक को सूचित कर दिया है कि उसे दस्तावेज डाक प्रमाणपत्र के अधीन अथवा पंजीकृत डाक से, एडी के साथ या बिना, भेजा जाए और इस हेतु बैंक में पर्याप्त राशि जमा करा दी है, तो दस्तावेज और नोटिस को तब तक तामील होना नहीं माना जाएगा, जबतक उन्हें शेयरधारक द्वारा सूचित तरीके से नहीं भेजा गया है और ऐसी तामील, बैठक की सूचना के संबंध में ऐसी सूचना वाले पत्र के पोस्ट करने के 48 घंटे पर्याप्त से तामील माना जाएगा और अन्य किसी मामले में उस समय तामील माना जाएगा जो सामान्य अनुक्रम में डाक वितरण में लगता है.

(iii) भारत में बृहत् स्तर पर परिचालित किसी समाचार पत्र में यदि कोई नोटिस या दस्तावेज विज्ञापित किया जाता है तो वह बैंक के प्रत्येक शेयरधारी पर, जिसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है और जिसने सूचना देने हेतु भारत स्थित किसी जगह का कोई पता नहीं दिया है, विज्ञापित होने के दिन से ही तामील माना जाएगा.

(iv) बैंक द्वारा, संयुक्त नाम से जारी शेयर के शेयरधारियों में से रजिस्टर में दर्ज प्रथम संयुक्त शेयरधारी को तामील, नोटिस और दस्तावेज तथा इस तरह प्रेषित नोटिस उस शेयर के समस्त शेयरधारियों पर तामील होना माना जाएगा.

(v) किसी शेयर धारक की मृत्यु हो जाने या उसके दिवालिया हो जाने पर, बैंक किसी नोटिस या दस्तावेज की तामील शेयर के अधिकारी को, मृतक के प्रतिनिधि को उनके नाम या पद से, दिवालिया के समनुदेशी या अन्य समान वर्णानुसार इस प्रकार अधिकार का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत के अन्दर दिये गए पते पर डाक शुल्क का भुगतान कर डाक द्वारा कर सकता है तथा पता न दिए जाने पर मृत्यु अथवा दिवालियापन न होने की दशा में तामील किये जा सकने वाले अन्य तरीके से तामील कर सकता है.

(vi) यूनियन बैंक द्वारा दिये जाने वाले किसी भी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित अथवा मुद्रित हो सकते हैं.

अध्याय - III

डिपाजिटरी में रखी गयी बैंक की प्रतिभूतियां

47. डिपाजिटरी और बैंक के मध्य करार : बैंक, अपनी जारी की गयी प्रतिभूतियों के संबंध में सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक या अधिक डिपाजिटरी से करार कर सकता है.
48. प्रतिभागी और डिपाजिटरी के मध्य करार :
- (I) कोई प्रतिभागी डिपाजिटरी से उसके एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए करार कर सकता है. जिस डिपाजिटरी से करार किया जाएगा, वह उनमें से होनी चाहिए जिनकी सेवाएं लेने के लिए विनियम 47 के अंतर्गत बैंक ने सहमति दी है.
- (II) बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संबंध में डिपाजिटरी की सेवाएं लेने के लिए बैंक का कोई भी शेयरधारक प्रतिभागी के माध्यम से उस डिपाजिटरी द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में करार कर सकता है.
49. प्रतिभूति प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण
- (I) बैंक का कोई शेयरधारक या किसी प्रतिभूति का धारक, जिसने उपर्युक्त विनियम 48 के तहत करार किया है, उस प्रतिभूति प्रमाणपत्र को अभ्यर्पित कर देगा जिसके लिए डिपाजिटरी सेवाएं ली जानी हैं.
- (II) उक्त उप विनियम (I) के अनुसार प्रतिभूति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर बैंक प्रतिभूति प्रमाणपत्र निरस्त कर देगा और अपने अभिलेख में उस प्रतिभूति के पंजीकृत स्वामी के रूप में डिपाजिटरी का नाम लिख देगा और तदनुसार डिपाजिटरी को सूचित करेगा.
- (III) डिपाजिटरी, उक्त उप विनियम (II) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति पर अपने अभिलेख में हितकारी स्वामी के रूप में ऊपर उप विनियम (I) में उल्लिखित व्यक्ति का नाम दर्ज कर देगा.
50. डिपाजिटरी में रखी गयी प्रतिभूतियों के अंतरण का पंजीकरण :
प्रत्येक डिपाजिटरी बैंक से अंतरण की सूचना मिलने पर प्रतिभूति का अंतरण अंतरिती के नाम पर पंजीकृत करेंगे.
51. प्रतिभूति प्रमाण पत्र प्राप्त करने या प्रतिभूति को डिपाजिटरी के पास रखे रहने का विकल्प -
- (i) बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि या तो प्रतिभूति का प्रमाणपत्र प्राप्त करें या प्रतिभूति को डिपाजिटरी में रखा रहने दे.

- (ii) जब कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी में रखना चाहता हो तो बैंक उस डिपॉजिटरी को प्रतिभूतियों के आबंटन के ब्यौरे की जानकारी देगा तथा इस सूचना की प्राप्ति पर डिपॉजिटरी अपने रजिस्टर में एलॉटी का नाम उस प्रतिभूति के लाभार्थ स्वामी के रूप में दर्ज करेगा.
52. डिपॉजिटरी में प्रतिभूतियाँ प्रतिमोच्य रूप में -
डिपॉजिटरी द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियाँ भौतिकता से परे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रतिमोच्य रूप में होंगे.
53. लाभार्थ स्वामी के अधिकार :
लाभार्थ स्वामी सभी अधिकारों एवं लाभों का अधिकारी होगा तथा डिपॉजिटरी द्वारा धारित अपनी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी देयताओं के अधीनस्थ होगा.
54. लाभार्थ स्वामी का रजिस्टर :
(i) डिपॉजिटरी में धारित बैंक की प्रतिभूतियों के मामले में डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 या सेबी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक डिपॉजिटरी, लाभार्थ स्वामियों का एक रजिस्टर इन्डेक्स रखेगा.
(ii) बैंक द्वारा निर्धारित अंतराल पर डिपॉजिटरी लाभार्थ स्वामित्व के रजिस्टर एवं इन्डेक्स की अद्यतन प्रति बैंक को प्रदान करेगा.
55. किसी प्रतिभूति के मामले में डिपॉजिटरी से बाहर रहने का विकल्प :
(i) यदि लाभार्थ स्वामी किसी भी प्रतिभूति के मामले में डिपॉजिटरी से बाहर रहने का विकल्प चुनता हो तो वह तदनुसार डिपॉजिटरी को सूचित करेगा.
(ii) ऐसी सूचना प्राप्ति पर डिपॉजिटरी उक्त उप विनियम (i) के अनुरूप अपने रिकॉर्ड में उचित प्रविष्टियाँ करेगा एवं बैंक को सूचित करेगा.
(iii) डिपॉजिटरी से सूचना प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर एवं ऐसे शर्तों की पूर्तिपर तथा सेबी डिपॉजिटरीस एवं सहभागिता विनियम 1996 और/या डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 में निर्दिष्ट ऐसे शुल्क के भुगतान पर बैंक लाभार्थ स्वामी या अंतरिती (transferee) को प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करेगा.

अध्याय IV

शेयरधारकों की बैठकें

56. वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन की सूचना

- (i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कोई प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शेयरधारकों की सामान्य बैठक के आयोजन की नोटिस बैठक के कम से कम 21 दिन पहले या दैनिक समाचार पत्रों में जिनका भारत में व्यापक परिचालन है, में प्रकाशित किया जाएगा.
- (ii) ऐसे प्रत्येक नोटिस में बैठक का समय, दिनांक एवं स्थान तथा बैठक में संपादित किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए.
- (iii) ऐसी बैठक के समय एवं दिनांक का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा. बैठक का आयोजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय के स्थान पर किया जाएगा.

57. विशेष साधारण बैठक

- (i) बोर्ड के निर्देशानुसार या केंद्रीय सरकार या सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत या शेयरधारित अन्य शेयरधारकों से ऐसी बैठक के आयोजन की माँग पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक का कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक का कोई भी एक निदेशक शेयरधारकों की एक साधारण बैठक का आयोजन कर सकते हैं.
- (ii) उपर्युक्त उप-विनियमन (i) में संदर्भित माँग में इस विशिष्ट सामान्य बैठक के आयोजन का प्रयोजन सूचित किया जाना चाहिए लेकिन इसमें अधिक माँग कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित समान फार्म में विभिन्न दस्तावेज शामिल हो सकते हैं.
- (iii) जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से शेयर धारित करते हैं, तो एक या अधिक द्वारा हस्ताक्षरित बैठक के नोटिस या माँग पर इस विनियमन के उद्देश्य के लिए वही प्रभाव रहेगा जैसाकि सभी द्वारा हस्ताक्षरित के मामले में होता.
- (iv) विशिष्ट सामान्य बैठक के समय, दिनांक एवं स्थान का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा. तथापि, केन्द्रीय सरकार या अन्य शेयरधारक की माँग पर की जानेवाली विशेष सामान्य बैठक माँग की प्राप्ति के 45 दिनों में आयोजित की जाएगी.
- (v) यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक जो भी मामला हो, उप-विनियमन (iv) के पुस्तक में निर्धारित अवधि के अंदर उप-विनियमन (i) द्वारा अपेक्षित बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में माँगकर्ताओं द्वारा स्वयं बैठक का आयोजन माँग की दिनांक से तीन माह के भीतर किया जा सकता है

तथापि, इस विनियमन की कोई बात ऊपर उल्लेखित तीन माह के अवधि की समाप्ति के पूर्व विधिवत् आयोजित बैंक के, अवधि की समाप्ति के पश्चात की किसी तारीख के लिए स्थगन पर रोक नहीं मानी जाएगी।

- (vi) माँगकर्ता द्वारा उप-विनियम (V) के अधीन बुलायी गयी बैठक यथा संभव उसी तरीके से आयोजित की जाएगी जिस रूप में बोर्ड द्वारा अन्य साधारण बैठकों का आयोजना किया जाता है।

58. साधारण बैठक का कोरम

- (i) शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कोई कारोबार नहीं किया जाएगा जब तक कि कारोबार की शुरुआत में उस बैठक में वोट होने के अधिकारी कम से कम 5 शेयरधारक स्वयं उपस्थित नहीं हैं।
- (ii) केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों की माँग पर बुलायी गयी बैठक के मामले में यदि बैठक के आयोजन के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो बैठक विसर्जित मानी जाएगी।
- (iii) अन्य मामले में यदि बैठक के आयोजन के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो बैठक स्थगित होगी एवं अगले सप्ताह के उसी दिन उसी समय एवं स्थान पर आयोजित की जाएगी या अध्यक्ष द्वारा निश्चित किसी अन्य दिन तथा समय एवं स्थान पर आयोजित की जाएगी। यदि स्थगित बैठक के दौरान बैठक के आयोजन के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर कोरम उपस्थित नहीं होता तो ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित शेयरधारक स्वयं या प्राक्सी या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधी को कोरम माना जाएगा तथा जिस कारोबार हेतु बैठक बुलायी गयी है उसको संपादित करेंगे।

तथापि, कोई भी वार्षिक साधारण बैठक ऐसी तिथि से आगे तक के लिए स्थगित नहीं की जाएगी जिसके अंदर अधिनियम के धारा 10(ए) (1) के अनुसार वार्षिक साधारण बैठक अवश्य की जानी चाहिए और यदि बैठक के आगामी सप्ताह के उसी दिन स्थगित होने का यह प्रभाव होता है, तब वार्षिक साधारण बैठक स्थगित नहीं की जायगी और कोरम उपस्थित होने पर नियत समय के एक घंटे के अंदर बैठक की कार्यवाही आरंभ होगी और उस समय उपस्थित शेयरधारक या प्राक्सी या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि को कोरम माना जाएगा।

59. साधारण बैठक में अध्यक्ष

- (i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक द्वारा एतदर्थ किसी विशेष बैठक में या सामान्यतः प्राधिकृत किये गये निदेशकों में से एक बैठक के लिए अध्यक्ष होंगे और यदि इस बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या एतदर्थ प्राधिकृत कोई निदेशक उपस्थित नहीं होते हैं तो बैठक द्वारा बैठक की अध्यक्षता हेतु बैठक में उपस्थित किसी अन्य निदेशक का कार्य

- (ii) साधारण बैठक का अध्यक्ष साधारण बैठकों की कार्यवाही नियंत्रित करेगा तथा उसे विशेषतः बैठकों में शेरधारकों के भाषण के लिए समय निर्धारण उनका क्रम निश्चित करना, यदि उसके मतानुसार किसी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है तो चर्चा का समापन तथा बैठक के स्थगित करने का उसे अधिकार होगा.

60. साधारण बैठकों में उपस्थिति हेतु अधिकारी व्यक्ति

- (i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सभी निदेशक एवं सभी शेरधारक उप विनियमन (ii) के प्रावधानों के अध्यक्षीन साधारण बैठक में उपस्थित रहने के अधिकारी हैं.
- (ii) साधारण बैठक में उपस्थित होनेवाले शेरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) या निदेशक अपनी पहचान एवं वोटिंग अधिकार को निश्चित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्धारित फार्म में, जिसमें निम्नजानकारी है, हस्ताक्षर करके बैंक को सुपुर्द करें :-

(ए) अपना पूर्ण नाम एवं पंजीकृत पता

(बी) अपने शेरों के पहचान क्रमांक

(सी) क्या वह वोट देने का अधिकारी है तथा वह व्यक्तिगत रूप में या प्राक्सी रूप में या विधिवत प्रतिनिधि के रूप में कितने वोट देने के लिए पात्र है.

61. साधारण बैठकों में वोटिंग

- (i) किसी भी साधारण बैठक में जबतक की मत विभाजन की माँग न की जाएं, संकल्प को हाथ उठाकर पारित किया जाएगा.
- (ii) अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, साधारण बैठक में प्रस्तुत सभी मामलों का निर्णय बहुमत के द्वारा किया जाएगा.
- (iii) उपविनियम (i) के अंतर्गत मत विभाजन की माँग न किये जाने पर, बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प के एकमत से या विशेष बहुमत से पारित होने या न होने की घोषणा, तथा कार्रवाई के कार्यवृत्त की पुस्तिका में इस आशय की प्रविष्टि, उस संकल्प के पक्ष या विपक्ष डाले गये मतों की संख्या या अनुपात के सबूत के बगैर, निर्णायक साक्ष्य होगी.
- (iv) हाथ उठाकर किसी भी संकल्प पर वोटिंग के परिणाम की घोषणा के पूर्व या घोषणा के समय, बैठक के अध्यक्ष स्वयं के प्रसताव मत विभाजन का आदेश दे सकते हैं तथा किसी शेरधारक या व्यक्तिगत रूप में उपस्थित शेरधारकों या प्राक्सी द्वारा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में धारित संकल्प के संबंध में शेर जो कुल वोटिंग प्राधिकार के 1/5 से अनाधिक संकल्प पर वोट करने का अधिकार देता है, उनकी ओर से बैठक की अध्यक्षता करने हेतु आदेश दिया जा सकता है.
- (v) मत विभाजन की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय मत विभाजन की माँग को वापस लिया जा सकता है.

- (vi) बैठक के स्थगन के प्रश्न पर या बैठक के अध्यक्ष के चयन के लिए मत विभाजन की मांग को तत्काल पूरा किया जाएगा.
- (vii) अन्य किसी प्रश्न पर मत विभाजन की मांग को मांग किए जाने के समय से 48 घंटे के अंदर बैठक के अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरा किया जा सकता है.
- (viii) किसी व्यक्ति के वोट देने की योग्यता तथा साथ ही मत विभाजन के मामले में किसी व्यक्ति द्वारा हाले जानेवाले वोट की संख्या के अंतिम निर्णय का अधिकार बैठक के अध्यक्ष का होगा.
62. साधारण बैठक के कार्यवृत्त :
- (i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समाप्त कार्यवाही के कार्यवृत्त को एतदर्थ रखी गयी पुस्तिका में दर्ज किया जायगा.
- (ii) ऐसा कोई भी कार्यवृत्त, यदि आयोजित कार्यवाही के बैठक के अध्यक्ष द्वारा या आगामी बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना है, तो वो कार्यवाही का साक्ष्य होगा.
- (iii) जब तक अन्यथा प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक यह माना जाएगा कि जिन साधारण बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त इस प्रकार अंकित हैं वे विधिवत बुलाई गयी और आयोजित हुई हैं, और उनमें हुई सभी कार्यवाही वास्तव में हुई है.

अध्याय V

निदेशकों का चुनाव

63. साधारण बैठक में निदेशकों का चुनाव किया जाना :

- (i) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के (i) के अनुसार किसी निदेशक का चुनाव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साधारण बैठक में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा स्वयं किया जाएगा.
- (ii) जब किसी निदेशक का चुनाव किसी साधारण बैठक में किया जाना हो, इस आशय की नोटिस बैठक आयोजन की नोटिस में शामिल की जाएगी. ऐसी हर नोटिस में, चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या तथा जिन शक्तियों के लिए चुनाव किया जाना है उन का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा.

64. शेयरधारकों की सूची -

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-नियम (i) के अंतर्गत निदेशकों के चुनाव के प्रयोजन के लिए, रजिस्टर में अंकित उन शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक चुना जाना है.

- (ii) इस सूची में, शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, जिस दिन शेयर पंजीकृत किए गए उसकी तारीख सहित उनके द्वारा रखे गए शेयरों के नंबर तथा डिनोटिंग नंबर, एवं बैठक की निश्चित की गई तारीख, जिस दिन चुनाव होना हो, उन मतों की संख्या जिसके लिए वे पात्र हों, समाहित होगा तथा प्रधान कार्यालय में आवेदन देने पर बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा निश्चित की गई कीमत पर बैठक की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले सूची की प्रतियां खरीद के लिए उपलब्ध होंगी।

65. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- (i) किसी उम्मीदवार का निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा, जबतक कि
- (ए) यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर का शेयरधारक न हो.
- (बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख को योजना या अधिनियम के अंतर्गत यह निदेशक होने के लिए अयोग्य न हो.
- (सी) कॉल के भुगतान के लिए निश्चित की गई अंतिम तारीख को या उससे पहले उसने स्वयं या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में सभी कॉल का भुगतान कर दिया हो.
- (डी) नामांकन लिखित रूप में हो और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए अधिकार रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारक या उनके विधिवत रूप से नियुक्त अटर्नियों द्वारा हस्ताक्षरित हो लेकिन कंपनी शेयरधारक द्वारा नामांकन उस कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाएगा. और ऐसा किया जाने पर जिस बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रमाणित की गयी सत्य प्रति, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी तथा ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.
- (ई) नामांकन के साथ या उसके अंदर किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या एश्वोरंस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य गजटेड अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया गया घोषणापत्र होना चाहिए, जिसमें उसने यह घोषणा की हो कि यह नामांकन स्वीकार करता है, तथा यह चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तथा उसे अधिनियम या योजना या उन विनियमों के अंतर्गत निदेशक बनने से अयोग्य करार नहीं किया गया है.
- (ii) कोई भी नामांकन जो सभी तरह से पूर्ण संबंधित दस्तावेजों सहित बैठक के लिए निश्चित की गई तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय में किसी कार्यदिन को प्राप्त नहीं होगा, मान्य नहीं होगा.

66. नामांकन की जांच :

- (i) नामांकन प्राप्ति के लिए निश्चित की गई तारीख के बाद के अगले कार्यदिवस में नामांकनों की जांच की जाएगी तथा यदि कोई नामांकन मान्य नहीं पाया जाता है, तो उसके कारण को दर्ज करने के पश्चात् उसे रद्द कर दिया जाएगा. यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली किसी रिक्ति विशेष के लिए केवल एक ही मान्य नामांकन हो तो, इस प्रकार नामित उम्मीदवार चयनित माना जाएगा तथा उसका नाम तथा पता चुने गए उम्मीदवार की तरह प्रकाशित किया जाएगा. ऐसे मामले में, उस प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक में चुनाव नहीं होगा, तथा यदि बैठक केवल उक्त चुनाव के लिए ही आयोजित की गई हो तो यह रद्द हो जाएगी.
- (ii) चुनाव किये जाने पर, चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक मान्य नामांकन होने के कारण, जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त होंगे, उसे चुना हुआ माना जाएगा.
- (iii) मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशक द्वारा, जिस दिन उन्हें चुना गया या चुना हुआ माना जाए उसकी अगली तारीख से कार्यभार ग्रहण किया गया माना जाएगा.

67. चुनाव विवाद :

- (i) यदि चुने हुए माने गए या घोषित किए गए किसी व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता या किसी निदेशकों के चुनाव की वैधता के बारे में कोई शंका या विवाद खड़ा होता है तो कोई भी हितबद्ध व्यक्ति चाहे वह उम्मीदवार हो या ऐसे चुनाव में मत देने को पात्र शायरधारक हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की

घोषणा की तारीख से सात दिनों के अंदर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को, चुनाव की वैधता के बारे में अपने संदेहों या विवादों के आधार के पूर्ण ब्यौरे लिखित रूप में सूचित करे.

- (ii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, ऐसी शंका या विवाद को निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) तथा (सी) के अंतर्गत नामित किन्हीं दो निदेशकों तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक की समिति को सौंप देगा.
- (iii) उप-विनियम (ii) में उल्लिखित समिति जैसा उन्हें आवश्यक लगे, मामले की जांच करेगी तथा यदि यह पाती है कि, चुनाव वैध था तो यह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि यह पाती है कि, चुनाव वैध नहीं था, तो समिति जांच शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उन परिस्थितियों में उचित प्रतीत होने वाला, पुनः चुनाव कराने सहित कोई आदेश या निर्देश देगी.
- (iv) इस विनियम के अनुसार, ऐसी समिति के आदेश तथा निर्देश, निर्णायक होंगे.

अध्याय VI

शेयरधारकों का मताधिकार

68. मताधिकार निर्धारण :

- (i) अधिनियम की धारा 33 (2ई) में निहित प्रावधानों के तहत, साधारण बैठक की तारीख से पहले रजिस्टर के बंद होने की तारीख को, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया हो, के पास हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा, तथा मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा.
- (ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के तहत, उक्त के अनुसार मत देने का पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो एक कंपनी नहीं है, और जो स्वयं या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित हो, तो उसके पास हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान के मामले में, उपर उप-विनियम (i) में बतलाए अनुसार उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा.

व्याख्या : इस अध्याय के लिए 'कंपनी' से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है.

- (iii) साधारण बैठक में उपस्थित रहने तथा मत देने का पात्र बैंक का शेयरधारक, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति (चाहे यह शेयरधारक हो या न हो) को बैठक में उपस्थित होने तथा अपने बदले मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है, परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.

69. विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- (i) केन्द्र सरकार या किसी कंपनी के शेयरधारक होने पर, जैसा भी मामला हो, वे एक प्रस्ताव द्वारा, अपने किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, शेयरधारकों की साधारण बैठक में उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने को प्राधिकृत कर सकते हैं, तथा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उल्लिखित) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के व्यक्तिगत शेयरधारक की तरह ही, केन्द्र सरकार या कंपनी, जिसका यह प्रतिनिधित्व

करता है, की तरफ से उन समान अधिकारों का उपयोग करने को पात्र होगा, इस प्रकार का प्राधिकार, दो व्यक्तियों को वैकल्पिक रूप से दिया जा सकता है और इस मामले में इनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा.

- (ii) कोई भी व्यक्ति तबतक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में एक कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित या प्रतिनिधि मत नहीं दे सकता जबतक कि, उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की उस बैठक जिसमें वह पारित किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी गयी हो.

70. प्रॉक्सी

(i) प्रॉक्सी संबंधी कोई भी लिखत तबतक मान्य नहीं होगा, जबतक व्यक्तिगत शेरधारक के मामले में यह, उसके द्वारा या उसके विधियत रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या संयुक्त धारकों के मामले में, वह रजिस्टर में जिसका पहले नाम हो, उस शेरधारक द्वारा या उसके विधियत रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या निगमित निकायों के मामले में यह उसके अधिकारी या विधियत रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

अर्थात् कि, प्रॉक्सी संबंधी लिखत किसी शेरधारक के द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होगा, जो किन्हीं कारणवश, अपना नाम न लिख सकता हो, और यदि उसकी मोहर लगा दी गयी हो तथा उसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार एवं सबरजिस्ट्रार ऑफ एश्योरंस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो.

(ii) कोई भी प्राक्सी लिखत तबतक मान्य नहीं होगी जब तक कि उस पर किये गये हस्ताक्षर के प्राधिकार संबंधी किसी मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकारपत्र, या उसकी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, यदि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पूर्व में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा और पंजीकृत न कराया गया हो, के साथ विधियत स्टांप युक्त प्रति, बैठक के लिए निर्धारित तिथि के चार दिन पूर्व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यालय में जमा न करा दी गयी हो.

(iii) कोई भी प्रॉक्सी लिखत तबतक मान्य नहीं होगी जबतक कि यह फॉर्म 'बी' में न हो.

(iv) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.

(v) प्रॉक्सी संबंधी लिखत में वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदान किये जाने के मामले में एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएं.

(vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी संबंधी लिखत का प्रदानकर्ता, जिस बैठक के लिए उसने प्राक्सी लिखत प्रदान की हो, उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं कर सकता है.

(vii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी या कर्मचारी विधियत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.

डी.पी. गुप्ता, स.म. प्रबन्धक

[विज्ञापन सं. 3/4/असाधारण/53/2000]

**UNION BANK OF INDIA
DRAFT OF PROPOSED REGULATIONS**

Mumbai, the 28th April, 2000

Union Bank of India General Regulations, 1998

In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of Union Bank of India after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :

CHAPTER I

INTRODUCTORY

1. Short title and commencement -

- (i) These regulations may be called Union Bank of India General Regulations, 1998.
- (ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions - In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof -

- (a) "Act" means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);
- (b) "Bank" means Union Bank of India, constituted under section 3 of the Act;
- (c) "Board" means the Board of Directors constituted under section 9 of the Act;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (e) "Committee" means a Committee as constituted by the Board;
- (f) "Executive Director" means the wholetime Director, not being the Managing Director;
- (g) "General Manager" means General Manager of the Bank;
- (h) "Management Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;
- (i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank;
- (j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer floppies or diskettes under sub-section (2B) of section 3 of the Act;

(k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for -

- (i) collecting applications from investors in respect of an issue,
- (ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities,
- (iii) assisting the Bank in -
 - (a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange,
 - (b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities,
 - (c) processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of issue, and
- (iv) such other function as assigned from time to time by the Bank,

(l) "Scheme" means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970;

(m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank;

(n) "Share transfer agent" includes -

- (i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or
- (ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (i);

(o) words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act;

(p) Other expressions used and not defined in these regulations but used in the Act or the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme.

CHAPTER II
SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of shares - The shares of Union Bank of India shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. Kinds of share capital

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of Union Bank of India which fulfills both the following conditions :

(A) as respect dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and

(B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely :

(a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (A) up to the date of winding up or repayment of capital, and

(b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be construed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register

(i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of section 3 of the Act.

(ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

(iv) Subject to the proviso of sub-section 2(D) of Section 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

(v) No Notice of any trust express implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. **Control over shares and registers** - Subject to the provisions of the Act and these regulations and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the head office of Union Bank of India and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.
7. **Parties who may not be registered as shareholders** -
- (i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.
- (ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.
8. **Maintenance of share register in computer system, etc.**
- (i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section 2(F) of section 3 of the Act, read with those mentioned in regulation 5, shall be maintained under sub-section 2(G) of section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic/optical/magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman & Managing Director or any other official not below the rank of General Manager designated in this behalf by the Chairman & Managing Director (hereinafter referred to as "the designated official").
- (ii) Particulars required to be entered in the share register under Section 3 (B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.
9. **Safeguards for protection of computer system**
- (i) The access to the system set out in Regulation 8(i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorised in this behalf by the Chairman & Managing Director or the designated official and the passwords if any, and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

- (ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman & Managing Director or the designated official.
 - (iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman & Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fire-proof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman & Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.
 - (iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back-up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.
 - (v) It shall be competent for the Chairman & Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and/or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.
10. Exercise of rights of joint holders - If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Union Bank of India except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.
11. Inspection of register
- (i) The register shall except when closed under Regulation 12, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.
 - (ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charge or if he requires a copy of computer prints of the register or of any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 100 words or fractional part thereof required to be copied.
 - (iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register

The Bank may, after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates -

(i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(ii) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

(iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificates on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in sub-clause (ii) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates

(i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the Bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renewal of share certificates

(i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or the Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee thinks fit, and on publication in two newspapers and on payment to Union Bank of India of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate..

16. Consolidation and sub-division of shares

On a written application made by the shareholder(s), the Board or the Committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/sub-division as the case may be and issue a new certificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17. Transfer of shares

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in form 'A' annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee alongwith the relative share certificate.

(ii) The instrument of transfer alongwith the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof.

(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer alongwith a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the Committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar and/or Share Transfer Agents for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar and/or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer alongwith the share certificate if any to the Transferee for resubmission unless :

(a) The instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

(b) The Registrar is satisfied that the transferee is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer.

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall unless it declines to register the transfer under regulation 19 hereinafter cause the transfer to be registered.

18. Power to suspend transfers - The Board or the Committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration of transfer of shares

(i) The Board may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other grounds :

(a) the transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;

(b) the transfer of shares, in the opinion of the Board is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest;

(c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force;

- (d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided however, that the powers of refusal mentioned in sub-regulation (i) (c) above may be exercised by the committee designated by the Board in this behalf.

- (ii) The Board shall after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i) -
- (a) if it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration; and
- (b) if it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i), intimate the Transferor and the Transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the Transfer Form.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency, etc.

- (i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by Union Bank of India as having any title to such share.
- (ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letters of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognised by Union Bank of India as having any title to such share.

(iii) Union Bank of India shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate, as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnify or otherwise as it may think fit.

(iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right -

(a) to be registered as a shareholder in respect of such share.

(b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. **Shareholder ceasing to be qualified for registration -** It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.
22. **Calls on shares -** The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.
23. **Calls to date from resolution --** A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.
24. **Notice of call -** A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.
25. **Extension of time for payment of call -** The Board may from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. **Liabilities of joint holders -** The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
27. **Amount payable at fixed time or by instalments as calls**
If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.
28. **When interest on call or instalment payable -** If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.
29. **Non-payment of calls by shareholder -** No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.
30. **Notice on non-payment of call or instalment -** If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, Union Bank of India may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by Union Bank of India by reason of such non-payment.
31. **Notice of Forfeiture -** The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default - If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.
33. Entry of forfeiture in the register - When any share has been forfeited under regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.
34. Forfeited shares to be property of Union Bank of India and may be sold - Any shares so forfeited shall be deemed to be the property of Union Bank of India and may be sold, reallocated or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.
35. Power to annul forfeiture - The Board may, at any time, before any share so forfeited under regulation 32 shall have been sold, reallocated or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.
36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest - Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to Union Bank of India all calls, instalments, interest, expenses or other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.
37. Partial payment not to preclude forfeiture - Neither a judgement nor a decree in favour of Union Bank of India for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by Union Bank of India of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by Union Bank of India in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.
38. Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank - The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share,

39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited - Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding regulations, the certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null and void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.
40. Application of forfeiture provisions - The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.
41. Lien on shares -
- (i) The Bank shall have a first and paramount lien -
- (a) on every share (not being a fully-paid share) for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;
 - (b) on all shares (not being fully-paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank;
 - (c) upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment fulfilment or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank over its lien.
- Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.
- (ii) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.
42. Enforcing Lien by Sale of Shares -
- (i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien :

(a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable; and

(b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(ii) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares - The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture - A certificate in writing under the hands of any director or any other officer of Union Bank of India duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchaser and allottee of forfeited share - Union Bank of India may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, reallocation or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, reallocated or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallocation or other disposal of the share and remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against Union Bank of India exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders -

(i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

(ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice.

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

- (iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.
- (iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.
- (v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.
- (vi) The signature to any notice to be given by the Union Bank of India may be written or printed.

CHAPTER IIISECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank - The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.
48. Agreement between a Participant and the depository
- (i) Any participant may enter into an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one whose services the Bank has agreed to avail of under Regulation 47.
- (ii) Any shareholder of the bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the form specified by such depository for availing its services in respect of securities issued by the Bank.
49. Surrender of certificate of security
- (i) Any shareholder or holder of any security of the bank who has entered into an agreement under regulation 48 above, shall surrender the certificate of security in respect of which he seeks to avail the service of a depository to the bank.
- (ii) The Bank on receipt of the certificate of security under sub-regulation (i) above, shall cancel the certificate of security and substitute in its record the name of the depository as a registered owner in respect of that security and inform the depository accordingly.
- (iii) A depository shall, on receipt of information under sub-regulation (ii) above, enter the name of the person referred to in sub-regulation (i) above, in its records as the beneficial owner.
50. Registration of transfer of securities with depository - Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.
51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository :
- (i) Every person subscribing to securities offered by the Bank, shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(ii) When a person opts to hold security with the depository, the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register name of the allottee as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in a fungible form - All securities held by the depository shall be dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner - The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of Beneficial Owner

(i) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act, 1996 or by SEBI in respect of securities of the bank held by the Depository.

(ii) The depository shall furnish to the Bank at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owners maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities

(i) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(ii) The depository shall on receipt of such intimation under sub-regulation (i) above make appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(iii) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfilment of such conditions and on payment of such fees as may be specified in the SEBI Depositories & Participants Regulations 1996 and/or the Depositories Act, 1996 issue a certificate of security to the beneficial owner or the transferee as the case may be.

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting—

- (i) A notice convening an annual general meeting of the shareholders signed by the Chairman & Managing Director or Executive Director or any authorised official of Union Bank of India shall be published at least twenty one clear days before the meeting in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.
- (ii) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting and also the business that shall be transacted at that meeting.
- (iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be held at the place of head office of Union Bank of India.

57. Extraordinary General Meeting—

- (i) The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board, or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying, in the aggregate not less than ten per cent of the total voting rights of all the shareholders.
- (ii) The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists
- (iii) Where two or more persons hold any shares jointly, the requisition or a notice calling a meeting, signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them
- (iv) The time, date and place of the Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board :

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholders shall be convened not later than 45 days of the receipt of the requisition.
- (v) If the Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (iv), the meeting may be called by the requisitionists themselves within three months from the date of the requisition :

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.
- (vi) A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting -

- (i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless a quorum of at least five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.
- (ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.
- (iii) In any other case, if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called :

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of section 10(A)(1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting -

- (i) The Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorised by the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the chairman of the meeting and if the Chairman & Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other director present to be the chairman of the meeting.

- (ii) The chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend general meetings—

- (i) All directors and all shareholders of Union Bank of India shall, subject to the provisions of sub-regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.
- (ii) A shareholder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the chairman containing particulars relating to—
- (a) his full name and registered address;
- (b) the distinctive numbers of his shares;
- (c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative.

61. Voting at general meetings—

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in Union Bank of India which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of general meetings—

- (i) Union Bank of India shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books, kept for the purpose.
- (ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were held or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.
- (iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings hereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at general meeting -

- (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 7 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in general meeting of Union Bank of India.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders -

- (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

- (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless
- (a) he is a shareholder holding 100 shares in Union Bank of India;
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed at least by one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of Union Bank of India and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of the Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of Union Bank of India on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

- (i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election disputes

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman & Managing Director of Union Bank of India and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director of Union Bank of India shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VIVOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights :

- (i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation : For this Chapter, "Company" means any body corporate.

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative -

- (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Union Bank of India. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Union Bank of India as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the head office of the Union Bank of India not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

(1) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing :

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar and Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an Officer of the Union Bank of India.

- (ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the head office of Union Bank of India not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Union Bank of India.
- (iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- (iv) An instrument of proxy deposited with Union Bank of India shall be irrevocable and final.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- (vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

D. P. GUPTA, Asstt. General Manager
[ADVT No. 3/4/Extry/53/2000]